□□□□□ □□□□□

जनसत्ता 21 जुलाई, 2014 : आजादी के बाद हमने वयस्क मताधिकार पर आधारित भारतीय गणराज्य की स्थापना की□

मूल अवधारणा यह रही कि हम □क ऐसी व्यवस्था बना□ंगे जिसके केंद्र में रहेगा देश का नागरिक□ विधायिका उसके हित में कानून बना□गी, कार्यपालिका उन कानूनों के दायरे में नागरिकों को □क विधि-सम्मत सुशासन मुहैया करा□गी, सेना बाह्य दुश्मनों से देश की सुरक्षा की गारंटी करेगी, पुलिस नागरिकों के जान-माल की रक्षा करेगी□ विधि-सम्मत शासन में कोई त्रुटि हुई तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर मानवाधिकारों की रक्षा करेगी□ इस पूरी व्यवस्था का मूल तत्त्व यह कि जनता मालिक है और व्यवस्था को चलाने वाले लोग उसके सेवक□ लेकिन व्यवस्था को बना□ रखने का खर्च इतना भारी-भरकम हो जा□गा, इसकी कल्पना ही शायद किसी ने उस वक्त नहीं की थी□ सबों को स्मृति में होगा यह तथ्य कि आजादी के बाद विधायकों को राजधानी में रहने की सुविधा उतने ही दिनों के लि□ मिलती थी जितने दिन विधानसभा का सत्र चलता था□ उनसे उम्मीद की जाती थी कि शेष दिन वे अपने क्षेत्र में रहेंगे□ उनको आज की तुलना में वेतन सुविधा□ं भी कम मिलती थीं□ इसी तरह नौकरशाही को भी आज जितनी वेतन-सुविधा□ं नहीं मिलती थीं□ यानी देश की कुल आमदनी का □क हिस्सा ही व्यवस्था को चलाने के तामझाम पर खर्च होता था□

धीरे-धीरे व्यवस्था को चलायमान रखने का खर्च ब□ता गया और आज आलम यह है कि कुल बजट का ब□ा हिस्सा जनता के हित में न खर्च होकर, जनता के तथाकथित सेवकों पर खर्च होता है□ इसी को तकनीकी भाषा में योजना-मद और गैर-योजना मद के रूप में चिह्नित किया जाता है□ योजना मद यानी वास्तविक विकास योजनाओं पर होने वाला खर्च और गैर-योजना मद यानी मुख्यत: कर्मचारियों, अधिकारियों, सेना, पुलिस, जज, मुख्तार आदि के वेतन, ग्रैच्यूटी, पी□फ आदि पर होने वाला खर्च□

योजना-मद की तुलना में गैर-योजना मद की राशि निरंतर ब□ती जा रही है□ कहने को लि□ इस बजट में गैर-योजना मद में होने वाले खर्च में पिछले बजट से कुछ कमी हुई है, लेकिन कुल मिला कर वह खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुकी है□ यानी आमद का ब□ा हिस्सा जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में खर्च न कर योजनाओं को जो क्रियान्वित करेंगे, उन पर खर्च हो रहा है□

इस बार का कुल बजट-आकार 17,94,892 करो□ का है□ कर राजस्व के रूप में 9,77,258 करो□ की राशि आ□गी और गैर-कर राजस्व के रूप में 2,12,505 करो□ की□ और इस तरह जमा राशि में योजना-व्यय तो मात्र 5,75000 करो□ का है लेकिन गैर-योजना मद दो गुने से भी ज्यादा, 12,19,763 करो□ का□ और वह इसलि□ कि इस व्यवस्था का संचालन-खर्च बहुत बहुत ब□ता जा रहा है□ किसी भी विभाग के कुल आबंटन का ब□ा हिस्सा उस विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन-सुविधाओं पर ही खर्च हो जाता है□ मसलन, अगर हमें स्वास्थ्य सेवाओं पर सौ रुप□ खर्च करने हैं तो नब्बे रुप□ डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन पर ही खर्च हो जाते हैं□ और ऐसा इसलि□ कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की बात जाने दें, □क भारतीय की औसत आमदनी अगर हजार रुप□ प्रतिमाह है तो □क सरकारी सेवक की आमदनी कम से कम दस हजार रुप□ प्रतिमाह तो है ही□ सेवाकाल में मोटी तनख्वाह, पी□फ, ग्रैच्यूटी और अवकाश ग्रहण करने के बाद जीवन भर मिलने वाला पेंशन□

हम यह नहीं कहते कि सेवकों को सेवा का पारिश्रमिक न मिले, लेकिन थोड़ा यह तो ध्यान देना ही होगा कि हमारी आमद कितनी है और देश के आम आदमी का जीवन स्तर क्या है? बजट बनाते वक्त इस घोर असंतुलन को कम करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जब सत्ता की चाभी ही नेताओं और अधिकारियों के हाथ में है तो वे अपनी सुविधाओं में निरंतर इजाफा क्यों न करें? इस बार भी निसंकोच कैबिनेट के खर्चे में 15.6 फीसद का इजाफा किया गया है।

कितनी घनघोर बहस चली है बजट पर! भाजपा के नेता इसे प्रगतिशील बजट बता रहे हैं, कांग्रेस के नेता अपनी आर्थिक नीतियों की नकल, कम्युनिस्ट पार्टियां जनता के हितों के प्रतिकूल। मध्यवर्ग को अब भी असंतोष है और कॉरपोरेट जगत को जितनी उम्मीद थी उतना 'सुधार' नजर नहीं आ रहा। हमारे लिए यह बजट अपने पूर्ववर्ती बजटों से दिशा और दृष्टि के हिसाब से खास भिन्न नहीं, उससे भी ज्यादा हमारे समक्ष यह दहकता प्रश्न है कि पिछले सड़सठ वर्षों में एक-एक प्रखंड में करोड़ों-करोड़ रुपए विकास मद में खर्च किए जा चुके। लेकिन गांवों की तस्वीर क्यों नहीं बदलती? हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रामीणों का सहारा खेती-बाड़ी है, लेकिन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी क्यों नहीं होती?

वजह यह है कि बिना जनता की भागीदारी के योजनाएं बनती हैं और योजनाओं के तहत किसी वीरान इलाके में पुलिया, यात्री शेड, ग्राम पंचायत भवन आदि बन जाते हैं, लेकिन वहां झाड़ू लगाने वाला, दीया-बाती जलाने वाला भी कोई नहीं होता। धीरे-धीरे वे खंडहर में बदल जाते हैं। क्योंकि थोपी गई उन योजनाओं से जनता का कोई लगाव नहीं होता। वे महज लूट का सबब हैं। ऐसी ही योजनाएं बनती हैं जिनमें लूट का अवसर ज्यादा हो।

कुल बजट का बड़ा हिस्सा तो गैर-योजना मद यानी वेतन, सुविधा, ग्रैच्यूटी, पेंशन आदि पर खर्च हो जाता है। दूसरी तरफ, जो राशि योजना मद के तहत विकास योजनाओं के नाम पर खर्च होती है, उसका बड़ा हिस्सा कमीशनखोरी में चला जाता है। इसकी जांच-पड़ताल के लिए किसी आयोग के गठन की जरूरत नहीं। यह तो सामान्य तथ्य है। दस्तूरी है। बीस से चालीस फीसद तक कमीशनखोरी तो 'ईमानदार' नेता और नौकरशाह भी करता है; भ्रष्टाचार का मामला तब बनता है जब कुल राशि का साठ-सत्तर फीसद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए! इसलिए कुल बजट की एक तुच्छ-सी राशि जनता के हित के काम में लगती है और वह भी बिना उसकी भागीदारी के बेमतलब होती है। आप गौर यह भी कर सकते हैं कि गैर-योजना मद की राशि तो शत-प्रतिशत खर्च हो जाती है, लेकिन योजना-मद की राशि राज्य सरकारें खर्च ही नहीं कर पाती हैं।

मोदी सरकार ने इस बार के बजट में ऐसी ही योजनाओं के लिए आबंटन किया है जिनमें लूट की अपार संभावनाएं हैं। सड़क निर्माण पर 38000 करोड़, स्मार्ट शहर पर 7060 करोड़, कृषि योजनाओं पर 7,500 करोड़, गंगा की सफाई पर 2037 करोड़। सड़क निर्माण नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों की कमाई का एक बहुत आसान माध्यम है। झारखंड में कोल्हान क्षेत्र की एक सड़क के निर्माण को लेकर ही अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा में तलवारें खिंचीं, जिसकी परिणति अर्जुन मुंडा सरकार के पतन में हुई और मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने थे।

गंगा की सफाई पर होने वाले ताजा आबंटन को डूबना ही है। गंगा की समस्या यह है कि उसका सहज-स्वाभाविक प्रवाह उत्तराखंड की जल परियोजनाओं की वजह से अवरुद्ध हो गया है, सामान्य दिनों में उसमें पानी कम रहता है और बरसात में पहाड़ों के क्षरण के साथ भारी मात्रा में गाद भी नीचे बह कर आती है। इसके अलावा जिन रास्तों से वह गुजरती है, करीब के शहरों का मल-जल, गंदी नालियां उसमें आकर गिरती हैं। कानपुर के बाद वह बेहद प्रदूषित हो जाती है। उसके भीतर जमा गाद की सफाई हो, लेकिन बड़ी समस्या शहरों के मूल उपभोक्तावादी चरित्र से जुड़ी है। उस दिशा में सरकार की कोई दृष्टि ही नहीं दिखाई देती। मतलब साफ है कि वह पूरी राशि हर-हर गंगे की भेंट चढ़ने वाली है।

कृषि क्षेत्र के योजना-मदों पर जरा गौर करें। कृषि क्षेत्र की मूल समस्या सिंचाई सुविधा का निरंतर कम होते जाना है। थार का विस्तार है। दक्षिण भारत में

सचिाई सुवधिाओं पर ध्यान दयिा गया, इसलि वहां साल-भर कुछ न कुछ कृषि-कार्य चलता रहता है। लेकनि उत्तर भारत में, कुछ इलाकों को छो, बारशि केपानी पर ही कसिान नरि्भर रहता है। दूसरी तरफबा की तबाही कैसे पानी का संचय हो, उसे खेतों तकपहुंचाया जा सके, इसकी कोई कार्य-योजना बजट में नजर आती है?

सा सात हजार करो रुप कृषिक्षेत्र केलि आबंटति कि ग है। इसमें से पांच सौ करो की धनराशि गांवों को इंटरनेट से जो ने पर खर्च होगी। सौ करो रुपया कसिान टीवी पर, पांच हजार करो रुपया कृषि भंडारण पर, 3600 करो रुपया पेयजल योजनाओं पर। हर योजना ऐसी जसिमें कमाई का अपार अवसर। टीवी खरीदि, इंटरनेट का साजो सामान और सबमें कमीशन खाइ। वकिास नीतिकी वजह से भूमगित जल-स्तर भागा जा रहा है, लेकनि करीब केनदी-नाले में बोरगि बैठाइ, पाइप को पानी टंकियों में ले जाइ। योजना कामयाब हो न हो, नरि्माण-कार्यों में कमाई ही कमाई। पांच हजार करो रुपया कृषि भंडारण केलि खर्च होने वाला है। शायद गोदाम बनाने, कोल्ड स्टोरेज बनाने आदि पर यह राशि खर्च होगी।

इस तरह नरि्माण-कार्य और खरीद पर सरकार का सारा जोर है। अपने रांची में ठीकपरियालाल चौकपर कवशिाल बहुमंजलि, कई खंडों वाला सदर अस्पताल बना है। लेकनि अगर आप चाहें कि उस सरकारी अस्पताल में क्स-रे हो जा, या दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थति में आपका भरोसे का इलाज, तो संभव नहीं। बस कवशिाल इमारत बन गई और खरीद का कहास्यास्पद उदाहरण यह कि वहीं के कस्वास्थ्य मंत्री ने अपने कार्यकाल में इतना अधकि कंडोम खरीद लयिा कि वह कई वर्षों तक खर्च नहीं होने वाला। ये सभी मामले जांच केदायरे में है। और यहां इसका जक्रि महज यह बताने केलि मंत्रयिों की सर्वाधकि रुचि नरि्माण-कार्य और खरीद वाली योजनाओं में रहती है, क्योंकि इनमें पैसा बनाने केखूब मौकेहोते हैं।

इस बजट में आदवािसयिों केप्रति घोर उपेक्षा और संवेदनहीनता झलकती है। भावी योजनाओं में आदवासी इलाकों की खनजि संपदा, वहां के जल-जंगल-जमीन की भारी भूमकि होने वाली है। लेकनि आदवासयिों केप्रति मोदी सरकार का नजरयिा क्या है, वह इस तथ्य से उजागर होता है कि आदवासयिों केलि वनबंधु कल्याण योजना केमद में महज सौ करो की राशि रखी गई है, जबकि पटेल की लौह प्रतमिा केलि दो सौ करो रुप।

साफ है कि बजट राशि का ब। हस्सिा संगठति क्षेत्र की सुख-सुवधिाओं और आमोद-प्रमोद पर खर्च होना है और योजना-मद की राशि बेमतलब की योजनाओं पर, जबकि वकिास केमोदी मॉडल केलि सरकार मूल रूप से वदिेशी नविेश पर नरि्भर रहेगी। कई क्षेत्रों में वदिेशी नविेश की अधकितम सीमा छब्बीस फीसद से ब। कर उनचास फीसद कर दी गई है। रेलवे तकमें वदिेशी नविेश को ब।वा देने की बात कही गई है। कुल मलिा कर इस बजट में बहुसंख्यक आबादी केलि न कोई उम्मीद है न संभावना।

फेसबुकपेज को लाइककरने केलि क्लकिकरें- https://www.facebook.com/Jansatta

ट्वटिर पेज पर फॉलो करने केलि क्लकिकरें- https://twitter.com/Jansatta